

प्रेषक,

अरविन्द सिंह हयांकी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-3

देहरादून : दिनांक 01 मार्च, 2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्यय में लोक निर्माण विभाग हेतु आयोजनागत पक्ष में नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किया जाना। महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक / प्रस्ताव सं0 4587/19 बजट (नाबार्ड वित्त पोषित कार्य) / 2016-17 दिनांक 31.01.2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्यय में अनुदान संख्या-22 की आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत 'वाह्य सहायतित योजना/ए0डी0बी0 वित्त पोषित कार्य' में हो रही सम्भावित बचत तथा नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना मद में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता को देखते हुए संलग्न बी0एम0-9 में उल्लिखित विवरणानुसार रु0 15.00 करोड़ (रुपये पन्द्रह करोड़ मात्र) की धनराशि व्यावर्तित करते हुए व्यय हेतु, आपके निर्वतन पर रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i)- इस सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि संलग्न पुनर्विनियोग प्रस्तावनुसार स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में नहीं किया जायेगा। इसका उपयोग नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजनागत वित्तीय वर्ष 2016-17 में गतिमान "जनपद टिहरी गढ़वाल में डोबरा-चांठी भारी मोटर सेतु का निर्माण" कार्य हेतु की गयी मांग के अनुसार किया जाय।
- (ii)- उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण वितरण अधिकारी द्वारा बी0एम0-4 प्रपत्र पर रखा जायेगा और पूर्व के माह के व्यय का विवरण अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय-12 के प्रस्तर-101 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर-113 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी (मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0) द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा। प्रशासनिक विभाग बजट मैनुअल के प्रस्तर-115 के अधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।
- (iii)- आयोजनागतपक्ष की उक्त योजनाओं की सी0सी0एल0 प्रत्येक त्रैमास में समय से निर्गत कर उसकी प्रति प्रत्येक त्रैमास में शासन को भी प्रेषित की जायेगी। विभागाध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि प्रत्येक खण्ड से समय से योजनाओं का विवरण प्राप्त करके समय से उसकी साख सीमा निर्गत कराये ताकि स्वीकृत की जा रही धनराशि का समय से उपयोग का विवरण प्राप्त करके समय से उसकी साख सीमा निर्गत कराये ताकि स्वीकृत की जा रही धनराशि का समय से उपयोग हो सके और योजना का लाभ जनता को प्राप्त हो सकें। जिस उत्तरदायी अधिकारी के द्वारा विलम्ब से विभागाध्यक्ष को योजनाओं का विवरण सूचित करने के कारण सी0सी0एल0 निर्गत करने में विलम्ब होता है तो उसका स्पष्टीकरण प्राप्त कर ठोस कारण न होने पर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी और लगातार दो बार योजनाओं का विवरण समय से न भेजे जाने के कारण यदि पुनः सी0सी0एल0 निर्गत करने में विलम्ब होता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। प्रमुख अभियन्ता का यह भी दायित्व होगा कि विभागीय योजनाओं की समय से समीक्षा कर समय से प्रतिशत के अनुसार सी0सी0एल0 निर्गत करेंगे।

(संलग्नक संख्या)
प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

- (iv)- वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड V भाग-1 के प्राविधानों के सभी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण होने के बाद ही आवश्यकता के अनुसार धनराशि आवश्यकता होने पर ही आहरित एवं वितरित की जायेगी।
- (v)- इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र 284/xxvii(1)/2013 दिनांक 30-03-2013 में उल्लिखित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (vi)- उत्तराखण्ड में लागू वित्तीय नियमों तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अधीन ही समस्त प्रक्रियायें पूर्ण की जायेंगी तथा ऐसे कार्य जो मानक के अनुसार 18 माह में पूर्ण होने चाहिये, ऐसे प्रकरणों में अधिवृद्धि या शेड्यूल रेड्स की दरों में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी।
- (vii)- साख सीमा मानक के अनुसार प्रत्येक त्रैमास में निर्गत की जायेगी तथा यदि मानक से अधिक साख सीमा की आवश्यकता हो तो तत्काल शासन से इस सम्बन्ध में अनुमति प्राप्त की जायेगी।
- (viii)- साख सीमा के आधार पर आवंटित धनराशि का एकमुश्त आवंटन आहरण वितरण अधिकारी/कार्य स्थल पर किया जाय एवं उसका पूर्ण विवरण बी0एम0 के प्रस्तर-10 में भरकर शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (ix)- जिन प्रकरणों पर शासन से पूर्वानुमति की आवश्यकता हो उन पर यथाशीघ्र सुस्पष्ट विवरण एवं प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (x)- वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-183/xxvii (1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में शासन स्तर से साफ्टवेयर के माध्यम से उक्तानुसार आयोजनागत पक्ष के सुसंगत उप मानक मदों में कुल धनराशि रु0 15.00 करोड़(रुपये पन्द्रह करोड़ मात्र) का बजट आबंटन लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22, के अन्तर्गत अलॉटमेन्ट आई0डी0 सं0 : S 1703220003 दिनांक 01.3.2017 द्वारा आपको आबंटित कोड सं0-4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है।
- (xi)- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्यय के अनुदान सं0-22 के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत लेखा शीर्षकों एवं प्राथमिक इकाईयों में नामें डाला जायेगा।
- (xii)- यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या: 1219/ xxvii (2)/2011 दिनांक 28 फरवरी, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
प्रभारी सचिव।

संख्या: 126 (1)/III(3)/2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम) ओबरोय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. एकीकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय (साईबर ट्रेजरी), 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड देहरादून।

आज्ञा/से,
(एस0एम0 टोलिया)
संयुक्त सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

Secretary, PWD (S038)

आवंटन पत्र संख्या -

अनुदान संख्या - 022

अलोटमेंट आई डी - S1703220003

आवंटन पत्र दिनांक 01-Mar-2017

HOD Name - Chief Engineer PWD (4227)

- 1: लेखा शीर्षक 5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
800 - अन्य व्यय
06 - नाबार्ड बिल्ट पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना के क

04 - जिला तथा अन्य सड़के

03 - राज्य सेक्टर

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	Plan Voted
			योग
24 - बृहत निर्माण कार्य	4000000000	1500000000	4150000000
	4000000000	1500000000	4150000000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

1500000000

(समस्त) (रिजिस्ट्रार)
सदर सचिव,
लोक निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड शासन।